(b) if so, what is the number of publi sector units referred to BIFR so far and in how many cases the revival of these units has come through; and

(c) whether not a single case of revival has come through, if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) The Board for Industrial and Financial Reconstluction (BIFR) has reported that it has registered 117 cases of sick public sector companies (52 Central and 65 State) as on June 30, 1994. The break-up of these cases is s under : a

	Central	State	Total
Reference registered	52	65	117
Dismissed as non-maintainable	2	20	22
Under inquiry	35	27	62
Rehabilitation schemes . . . . . approved/sanctioned by BIFR	1	4	5
Winding up recommended to the concerned High Courts .	1	4	5
Winding up notices issued.	9*	8	17
Draft schemes circulated	4	2	6

£ Of these four cases have been stayed by the High Courts.

In so far as the Central Public Sector Undertakings are concerned, Government have constituted a Group of Ministers to periodically review the performance of public sector enterprises particularly sick enterprises. The functions of the Group of Ministers include, inter-alia, to consider in respect of each of a sick public sector enterprise referred to BIFR, the proposed packeges of relief to be presented to the BIFR and give directions and guidelines to the Ministries/Departments for taking a stand or making commitment on behalf of Government of India before the BIFR.

विदेशी वालंटियर कार्यक्रम में शामिल मामले

976. मौलाना अबेदुल्ला खान आजमी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी वालंटियर कार्यक्रम में किन-किन मामलों को शामिल किया गया है ;

(ख) इनका कार्यान्वयन एवं निष्पादन पिछले साल और इस साल अब तक किस प्रकार से किया गया है; और

(ग) भारत को इससे किस प्रकार से लाभ हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतमें संयुक्त राष्ट्र स्वैच्छिक कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्रस्वैच्छिक कार्यक्रम एक बहुपक्षीय स्वयंसेवक भेजने वाला संगठन है और मध्यम और उच्चस्तर के विशेषज्ञ व्यावसायिकों को, जो 118 से भी अधिक विकासशील देशों में कार्यरत हैं, भेजने वाला संयक्त राष्ट्र का प्रमुख सप्लायर है।

(ख) संयुक्त राष्ट्र के स्वयंसेवकों की संविदा की शर्तों के अन्तर्गत सामान्यतया दो वर्षों के लिए मेजबान सरकार की सुस्पष्ट प्रार्थना पर कार्य सौंपा जाता है। भारत से जाने वाले अभ्यर्थियों की पहचान का कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा मामलों और खेल-कूद विभाग द्वारा किया जाता है और अन्तिम रूप से स्वीकृति हेतु नामांकन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा भेजा जाता है।

(ग) संयुक्त राष्ट्र स्वैच्छिक कार्यक्रम दक्ष और चुस्त पुरुष और स्त्रियों को विभिन्न देशों में विकास प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने का अवसर देता है। वर्तमान में, 96 भारतीय राष्ट्रिक संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक के तौर पर विदेशों में कार्य कर रहे हैं और 363 अभ्यर्थी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के रोस्टर में नियुक्ति की इंतजार में हैं।

संयुक्त स्टाक कंपनियों में अनियमितताएं

977. **मौ लाना औबैदुल्ला खान आजमी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त स्टाक कंपनियों द्वारा पिछले साल कुल कितनी पूंजी जारी की गई ;

(ख) सरकार ने उस पर किस तरह से नियंत्रण रखा ;

(ग) क्या कोई अनियमिततायें पाई गईं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1993 94 के दौरान कम्पनियों ने पब्लिक और राइट्स इश्यू के जरिए कुल 21,982 करोड़ रुपए की राशि जुटाई।

(ख) से (घ) पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम के 1992 में रद्द होने से, पूंजी बाजार में पूंजी जुटाने के लिए प्रवेश करने वाली कम्पनियों को सरकार से किसी भी प्रकार की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती लेकिन उन्हें भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करना होता है। "सेबी" अनियमितताओं की जांच करता है, उसके ध्यान में लाई गई निवेशक की शिकायतों पर ध्यान देता है और उपचारी कार्रवाई करने के लिए प्रयास करता है।

Irregularities in the Tender Submitted by a German Firm

978. SHRI O. P. KOHLI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the Hindustan Times of 27 June, 1994 under the caption 'Minting money over mint machinery' to the effect that a case of tampering and forgery has come to light in tender application submitted by a German company for the supply of a special type of machine in the mints for processing cupronickel and stainless steel coin blanks;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether the matter has been enquired into and if so, with results and the action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) There was no case of tampering or foregery found in the tender application submitted by any German company for the supply of special type of machine in the Mints for processing supronickel and stainless steel coin blanks has been brought out in the Hindustan Times of 27-6-1994 under the caption "Minting money over mint machinery". The allegations referred in the above news item are false nad totally baseless.